Public Sector (सार्वजनिक क्षेत्र)

सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, एवं समृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन भी रहा है। इसके लिए इस क्षेत्र द्वारा अवसंरचनाओं के विकास के साथ-साथ संतुलित को भी प्राथमिकता दी गई है। इस आधार पर यह कहा जाना तर्कसंगत होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र न केवल राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, बल्कि इसमें धन के संकेन्द्रण पर अंकुश लगाकर वितरण न्याय के संवैधानिक लक्ष्य के प्राप्ति में भी सहायता की है।

इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था में विकास और समृद्धि के महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान दी गई है, लेकिन जहाँ तक इसके कार्यप्रणाली का प्रश्न है, निश्चित रूप से 1991 में हुए उदारीकरण ने इसे व्यापक रूप में प्रभावित किया है। नई आर्थिक प्रणाली के आने के साथ ही इस क्षेत्र की इकाईयों में बाजोन्मुखी दृष्टिकोण शामिल करने के लिए न केवल उसमें संरचनात्मक सुधार किए गए बल्कि पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता देने की पहल की गई। इस क्रम में विनिवेश तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी संकल्पनाओं को देखा जा सकता है।

वर्तमान में निम्नांकित तीन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है

(1) परमाणु ऊर्जा
(2) परमाणु खनिज
(3) रेल परिवहन

इसके पूर्व अस्त्र-शस्त्र एवं प्रतिरक्षा उद्योग इसके लिए आरक्षित थे लेकिन मई 2001 में इस उद्योग में 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने से आरक्षित श्रेणी से बाहर

कर दिया गया है।

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन का प्रश्न है 1980 के दशक से सार्वजनिक क्षेत्र में ~~लगभग~~ ए घरेलू निवेश में लगभग 50% की कमी हुई। इसके बावजूद वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय सार्वजनिक इकाइयों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 11.68% तथा वर्ष 2005-06 मे 11.12% रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2006 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी द्वारा जारी आंकड़ों में यह उल्लेख किया गया था, कि घरेलू निवेश मे हुई कमी के बावजूद विशेषकर विद्युत तथा तेल क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों में उच्चस्तरीय कार्यकुशलता देखी गई है। लेकिन निश्चित रूप से राज्य विद्युत बोर्ड एवं सड़क परिवहन नियमों के कार्यनिष्पादन की अपर्याप्तता से इस क्षेत्र में वित्तीय समस्याएं बनी हुई है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, कार्यनिष्पादन में आने वाली समस्याओं में इनके उत्पादों की कीमतों का तार्किक नहीं होना भी शामिल है। विगत दो दशकों में इन कीमतों में लगभग 17% कमी दर्ज की गई है। अतः स्पष्ट है, कि इन समस्याओं के बावजूद इसके कार्य निष्पादन को संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी इकाइयों के मूल्यांकन का आधार केवल मौद्रिक लाभ नहीं हो सकता।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर चर्चा कीजिए तथा इस पृष्ठभूमि यह इंगित कीजिए कि इसमें किस प्रकार सुझाव अपेक्षित है 150 words